भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *†261

उत्तर देने की तारीख 20 मार्च, 2023 (सोमवार)

29 फाल्गुन, 1944 (शक)

प्रश्न

उत्तर पूर्वी राज्यों में अवसंरचना संबंधी विकास

*†261. श्री दिलीप शइकीया:

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क (कनेक्टिविटी) बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अवसंरचना से संबंधित किए गए विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देने हेतु किसानों के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 20.03.2023 को उत्तरार्थ लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *261 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) भारत सरकार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए स्कीम के डिजाइन के अनुसार अनुमोदित वित्तीय परिव्ययों के भीतर विभिन्न फ्लैगशिप और अन्य स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार 55 गैर-छूट प्राप्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अवसंरचना विकास सहित क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अपनी सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का कम से कम 10% खर्च करना अनिवार्य है। 10% जीबीएस के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 से इन केंद्रीय मंत्रालयों /विभागों द्वारा 3.84 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 10% जीबीएस के तहत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

10% जीबीएस के तहत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का वर्ष-वार विवरण (करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2014-15	36,108	27,359	24,819
2015-16	29,088	29,669	28,674
2016-17	29,125	32,180	29,368
2017-18	43,245	40,972	39,753
2018-19	47,995	47,088	46,055
2019-20	59,370	53,374	48,534
2020-21	60,112	51,271	48,564
2021-22	68,020	68,440	70,874
2022-23	76,040	72,540	47,785*
कुल	**4,49,103**	**4,22,893**	**3,84,426**

स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट का विवरण-11.

नोट: वास्तविक व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं और वित्त मंत्रालय की जांच के अधीन हैं।

* चालू वर्ष 2022-23 के लिए तीसरी तिमाही के अंत यानी 31.12.2022 तक सभी 55 मंत्रालयों/विभागों का कुल जीबीएस व्यय।

2014-15 में केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल व्यय 4,726 करोड़ रुपये था जो 2021-22 में बढ़कर 23,293 करोड़ रुपये हो गया है (392 प्रतिशत की वृद्धि)। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया गया व्यय 45,836 करोड़ रुपए है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा कई अवसंरचना विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः-

• **<u>सड़क कनेक्टिविटी:</u>**

पिछले 03 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 60,093 करोड़ रुपये की राशि के कुल 4,686 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही प्रमुख राजधानी सड़क संपर्क परियोजनाओं में नागालैंड में दीमापुर-कोहिमा रोड (77.87 किमी) को 4 लेन का बनाना; अरुणाचल प्रदेश में नगांव बाईपास को होलोंगी (167 किमी) तक 4 लेन का बनाना; सिक्किम में बागराकोट से पाकयोंग (एनएच-717ए) (152 किमी) तक वैकल्पिक दो लेन राजमार्ग; मिजोरम में आइजोल-तुईपांग राष्ट्रीय राजमार्ग-54 (351 किमी) को 2 लेन का बनाना; मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-39 (20 किमी) के इम्फाल-मोरेह खंड को 4 लेन का बनाना और 75.4 किमी को 2 लेन का बनाना शामिल है।

2019-20 से पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 3,067 बस्तियों को जोड़ने के लिए 21,893 करोड़ रुपये की लागत से 22,708 किलोमीटर की कुल सड़क लंबाई पूरी की गई है।

इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) और पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएसडीएस) के अंतर्गत 3,372.58 करोड़ रुपए की 77 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

• **<u>रेल कनेक्टिविटी:</u>**

पिछले तीन वर्षों के दौरान 77,930 करोड़ रुपये की लागत से 1,909 किमी की कुल लंबाई को कवर करते हुए पूरी तरह से/आंशिक रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाली 19 रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की गई हैं और वे आयोजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 409 किलोमीटर लंबाई चालू कर दी गई है और मार्च 2022 तक 30,312 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

• **<u>वायु कनेक्टिविटी:</u>**

नागर विमानन मंत्रालय ने देश में सेवा रहित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों से देश भर में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और हवाई यात्रा को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए 21.10.2016 को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उड़ान के तहत रूपसी, तेजू, तेजपुर, पासीघाट, जोरहाट, लीलाबाड़ी, शिलांग, पाक्योंग, ईटानगर और दीमापुर में हवाई अड्डों को शामिल करते हुए 64 मार्गों को प्रचालित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2014 में 9 हवाई अड्डे प्रचालनरत थे। वर्तमान में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 16 प्रचालनरत हवाई अड्डे हैं। इसके अतिरिक्त, जीरो में एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को भी चालू किया गया है।

- **<u>जलमार्ग कनेक्टिविटी:</u>**

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1,040.71 करोड़ रुपये की लागत से 4 जलमार्ग परियोजनाओं/कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**परियोजना / कार्य**	**लागत (करोड़ रुपए में)**
1	एन.डब्ल्यू.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) का व्यापक विकास	474
2	एन.डब्ल्यू.-16 (बराक नदी) का व्यापक विकास	148
3	पांडु (गुवाहाटी) में जहाज मरम्मत सुविधा का निर्माण और पांडु बंदरगाह (ब्रह्मपुत्र नदी) के लिए वैकल्पिक सड़क संपर्क का विकास	388
4	मिजोरम के लुंगलेई जिले में ख्वाथलंगतुईपुई - तुइचावंग नदी पर आईडब्ल्यूटी का विकास	6.18
5	त्रिपुरा में गुमटी नदी पर अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास	24.53
	कुल	**1,040.71**

- **<u>दूरसंचार कनेक्टिविटी:</u>**

दूरसंचार विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए इस क्षेत्र में कई परियोजनाएं शुरू की हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः-

(i) अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिले परियोजनाः इस परियोजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के 1,683 गांवों और असम के 2 जिलों (कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ) के 691 गांवों को अरुणाचल प्रदेश में 980 मोबाइल टावरों और असम के 2 जिलों (कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ) में 531 मोबाइल टावरों को स्थापित करके कवर किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना की लागत 1,255.59 करोड़ रुपये है।

(ii) मेघालय परियोजनाः इस परियोजना के अंतर्गत मेघालय राज्य में 889 मोबाइल टावरों की स्थापना करके 11 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ 1,164 गांवों को कवर किया जाना है। परियोजना की लागत 804.37 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत मेघालय के अतिरिक्त 723 गांवों को भी 167.59 करोड़ रुपये की लागत से 528 मोबाइल टावरों को स्थापित करके कवर करने का प्रस्ताव है।

(iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश (केवल राष्ट्रीय राजमार्ग) में अनकवर्ड गांवों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ निर्बाध कवरेज। इस योजना के तहत कुल 1,358 टावर चालू किए गए हैं।

(iv) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को उच्च गुणवत्ता और उच्च गति वाली इंटरनेट पहुंच उपलब्ध कराने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड (बीएससीसीएल), बांग्लादेश से कॉक्स बाजार/कुआकाटा के रास्ते अगरतला के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 20 जीबीपीएस अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ किराए पर लिया है। पहला 10 जीबीपीएस लिंक 26-11-2021 को चालू किया गया था और दूसरा 10 जीबीपीएस लिंक 21-04-2022 को चालू किया गया था। यह परियोजना सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के माध्यम से 17.15 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई थी।

(v) मोबाइल परियोजनाओं के अलावा देश में सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.6 लाख) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। अब परियोजना का दायरा सभी बसे हुए गांवों तक बढ़ा दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारत नेट परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल नियोजित ग्राम पंचायतें**	**बिछाया गया ओएफसी (किमी)**	**ओएफसी पर सेवा के लिए तैयार जीपी**	**सैटेलाइट पर सेवा के लिए तैयार जीपी**	**सेवा के लिए तैयार कुल जीपी (ओएफसी + सैटेलाइट)**
1	अरुणाचल प्रदेश	1,796	1519	79	885	964
2	असम	2,665	4877	1,506	5	1,511
3	मणिपुर	2,782	634	315	1,152	1,467
4	मेघालय	1,792	1069	122	560	682
5	मिजोरम	762	689	41	411	452
6	नगालैंड	983	2000	116	116	232
7	सिक्किम	185	942	26	9	35
8	त्रिपुरा	1,114	1686	587	142	729
	कुल	12,079	13,416	2,792	3,280	6,072

(vi) बीएसएनएल द्वारा यूएसओएफ से वितीय सहायता के साथ भारत नेट उदयमियों (बीएनयू) के माध्यम से भारत नेट का उपयोग करके देश भर के जीपी / गांवों (एनईआर सहित) में 5 लाख एफटीटीएच कनेक्शन शुरू करने के लिए एक पायलट परियोजना लागू की जा रही है। 14-03-2023 तक देश भर में इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुल 2,04,170 एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(vii) 4जी संतृप्ति परियोजना: इस परियोजना के तहत देश भर के 24,680 वंचित गांवों को 4जी सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसमें 6,279 गांवों में मौजूदा 2जी/3जी साइटों का 4जी सेवा में उन्नयन भी शामिल है। इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 5,665 गांव शामिल हैं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की स्थिति निम्नानुसार हैः

- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के 5,790 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।
- राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के सभी बसे हुए गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था।
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों ने 30.04 लाख घरों के 100 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण की सूचना दी है।

विद्युत मंत्रालय ने भी पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2014 से विद्युत उत्पादन (जल/थर्मल) परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, पारेषण और वितरण नेटवर्क को भी सुदृढ़ किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 740 मेगावाट की 03 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) शुरू की गई हैं। मैसर्स असम विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा असम राज्य में 69.755 मेगावाट क्षमता (7x9.965 मेगावाट) की गैस आधारित विद्युत परियोजना नामतः लखवा प्रतिस्थापन विद्युत परियोजना दिनांक 14.02.2018 को चालू की गई थी।

इसके अतिरिक्त, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) दो प्रमुख अंतर-राज्य विद्युत पारेषण और वितरण स्कीमें नामतः (i) 6,700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण प्रणालियों (33केवी और उससे अधिक) के सुदृढ़ीकरण के लिए छह राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड) के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी); और (ii) 9,129.32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक स्कीम कार्यान्वित कर रही है।

इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास (एनईएसआईडी) स्कीम के तहत 273.01 करोड़ रुपये की 06 विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 28.02.2023 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम (ग्रामीण क्षेत्रों सहित) में 578.54 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता स्थापित की गई है:

28.02.2023 की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की राज्य-वार संस्थापित क्षमता					
क्र.सं.	**राज्य**	**लघु जलविद्युत (मेगावाट)**	**बायो विद्युत (मेगावाट)**	**सौर विद्युत (मेगावाट)**	**कुल क्षमता (मेगावाट)**
1	अरुणाचल प्रदेश	133.11	0.00	11.64	144.75
2	असम	34.11	2.00	147.93	184.04
3	मणिपुर	5.45	0.00	12.28	17.73

4	मेघालय	32.53	13.80	4.15	50.48
5	मिजोरम	45.47	0.00	8.02	53.49
6	नागालैंड	31.67	0.00	3.04	34.71
7	सिक्किम	55.11	0.00	4.69	59.80
8	त्रिपुरा	16.01	0.00	17.53	33.54
	कुल (मेगावाट)	**353.46**	**15.80**	**209.28**	**578.54**

(ग) और (घ) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए 4 पूर्वोत्तर राज्यों नामतः असम, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड सहित 19 राज्यों में वाणिज्यिक फसलों अर्थात कपास, पटसन और गन्ने के संबंध में एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। असम और त्रिपुरा में जूट और कपास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। मेघालय और नागालैंड में जूट कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। यह स्कीम प्रदर्शनों और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए किसानों को सहायता प्रदान करती है। 2019-20 से 2022-23 तक इस स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को केंद्रीय हिस्से के रूप में निम्नानुसार 2,095.16 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है:

(लाख रु. में)

राज्य	**फसल**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**कुल**
असम	जूट	278.19	278.19	230.40	185.94	972.72
	कपास	26.91	14.90	15.30	14.13	71.24
	कुल	**305.10**	**293.09**	**245.70**	**200.07**	**1043.96**
त्रिपुरा	जूट	126.82	126.80	77.38	62.28	393.28
	कपास	71.38	71.38	54.90	51.64	249.3
	कुल	**198.20**	**198.18**	**132.28**	**113.92**	**642.58**
मेघालय	जूट	70.98	77.91	39.59	32.30	220.78
	कुल	**70.98**	**77.91**	**39.59**	**32.30**	**220.78**
नागालैंड	जूट	57.92	57.92	39.60	32.40	187.84
	कुल	**57.92**	**57.92**	**39.60**	**32.40**	**187.84**
कुल योग		**632.20**	**627.10**	**457.17**	**378.69**	**2095.16**

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और मसाला बोर्ड से संबंधित चार स्कीमें हैं जिनके अंतर्गत चाय, कॉफी, रबड़ और इलायची के रोपण/पुनःरोपण के लिए उत्पादकों/किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। ये स्कीमें चाय बोर्ड की "चाय विकास और संवर्धन स्कीम", कॉफी बोर्ड की "एकीकृत कॉफी विकास परियोजनाएं", रबड़ बोर्ड की "प्राकृतिक रबड़ का संवहनीय और समावेशी विकास" और मसाला बोर्ड की "मसालों में निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार

और इलायची के विकास के लिए एकीकृत स्कीम" हैं। । इन स्कीमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन फसलों की खेती हेतु सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं।

पिछले तीन वर्षों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 10% जीबीएस के तहत प्लांटेशन बोर्डों का वर्षवार व्यय (करोड़ रुपये में)			
कमोडिटी बोर्ड	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23 (तीसरी तिमाही तक)**
चाय बोर्ड	74.2	42.43	17.21
कॉफी बोर्ड	10.45	8.19	5.55
रबर बोर्ड	28.43	41.65	20.77
स्पाइस बोर्ड	7.63	8.49	8.49
कुल	120.71	100.76	52.02

*****